

जल संकट

सुबह-सुबह जिम पर जाते हुए रेड एफ एम 93.5 पर 'पानी याद दिला देंगे' कैम्पेन सुना, जिसके अनुसार नीति आयोग ने कहा है कि 2020 तक दिल्ली तथा अन्य मेट्रो शहरों का ग्राउण्ड वाटर लेवल शून्य हो जाएगा। जिसके लिए एफ एम अपने श्रोताओं को पानी का बेवजह उपयोग ना करने और अतिरिक्त पानी बेचने का आग्रह कर रहा है।

थोड़ी जांच पड़ताल की तो वर्ष 2019 की 'जल शक्ति मंत्रालय' तथा 'ग्रामीण विकास मंत्रालय' के सहयोग से निर्मित नीति आयोग के वर्ष 2019 की रिपोर्ट मिली, जिममें कुछ रोचक, कुछ वैज्ञानिक, तथा कुछ चुनौतीपूर्ण लक्ष्य सामने आये, आइए जरा इनपर नजर डालते हैं:-

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत पर वर्ष 2016 में मलजल एवं अस्वच्छता के कारण प्रति व्यक्ति रोग भार चीन एवं श्रीलंका से क्रमशः 40% एवं 12% अधिक था। यह अनुमान लगाया गया कि प्रति वर्ष 2 लाख व्यक्ति अस्वच्छ जल तथा जल की अनुपलब्धता के कारण कालकलवित होते हैं।

भारत विश्व की जनसंख्या के 17% का धारक है जबकि यहां मात्र 4% ताजे जल की उपलब्धता है। रिपोर्ट के अनुसार देश में उपलब्ध संचित जल का 690 बीसीएम जल सतही स्तर से तथा 447 बीसीएम भूमिगत जल से प्राप्त होता है, जबकि चिंताजनक रूप से भूमिगत जल का प्रयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, वही 214 बीसीएम अतिरिक्त वर्षा जल भूमिगत जल स्रोतों में संयोजित करने के लिए स्पष्ट रूप से उपलब्ध है।

एक अन्य अनुमान में पाया गया है कि कृषि क्षेत्र में वर्ष 2030 तथा पानी की खपत 570 बीसीएम तक पहुंच जाएगी जिसके कारण सिंचाई योग्य भूमिगत जल स्तर 62% से कम होकर 52% तक गिर जाएगा।

भारत में चावल और गन्ने जैसी अधिक पानी की खपत वाली फसलें उगाई जाती हैं, अकेले पंजाब में धान की खेती हेतु 80% भूजल का उपयोग कर लिया जाता है। यह विहार में धान उगाने में उपयुक्त पानी का 3 गुणा तथा पं० बंगाल में पानी का दो गुणा है।

एक अन्य रोचक तथ्य के अनुसार वर्ष 2014-15 में भारत से बासमती चावल के निर्यात के रूप में हमने 10 खरब लीटर से अधिक का पानी निर्यात किया जो दूसरे खाद्यानों गेहूं एवं बाजरे के लिए बहुत अधिक है।

वर्ष 2030 तक भारत की शहरी जनसंख्या बढ़कर 600 मिलियन तथा पहुंच जाएगी जिसके लिए पेयजल उपब्ध कराना चुनौतीपूर्ण कार्य है। विश्व के 20 बड़े जल की कमी वाले शहरों में से 5 शहर भारत के हैं जिनमें दिल्ली दूसरे स्थान पर है।

भारत में विद्युत ऊर्जा का 83% भाग आज भी थर्मल पावर पर आधारित है अर्थात कोयले के उपभोग वाले प्लांट पर। इनमें से 90% से अधिक में स्वच्छ जल का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2013-2016 के मध्य 20 में से 14 प्लांटों ने जल की अनुपलब्धता के कारण शूटडाउन का दंश झेला है। वर्ष 2030 तथा 70% थर्मल पावर जल की अनुपलब्धता का दंश झेंलेगे।

न सिर्फ जल की अनुपलब्धता बल्कि उसमें प्राकृतिक स्रोत से छेड़छाड़ भी भारत की जैवविविधता के लिए खतरनाक साबित हुई है। किसी नदी तंत्र पर बांध निर्माण ना सिर्फ नदी के प्रवाह को मंदा करता है बल्कि नदी में बांध निर्माण बढ़ाकर नदी के पोषण तत्वों को भी नष्ट करता है, जो उसकी सहायक नदियों के जीवन हेतु महत्वपूर्ण होते हैं।

भारत का प० घाट जो जैवविविधता के 325 पौधों एवं 190 प्रजातियों के फ्लोरा और फौना का उत्तरदायी है, काली नदी प्रोजेक्ट के निर्माण से वर्ष 1973-2016 के दौरान वन क्षेत्र 85% से घटकर 55% तक आ गया है। यह इस घाट के लिए अपूर्ण क्षति है।

ये आंकड़े जल का आपातकाल दर्शाने के लिए काफी हैं। जिनका संदर्भ लेते हुए कुछ राज्यों ने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं जैसे राजस्थान की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान।

वर्ष 2016 में राजस्थान में लांच एमएमजेएसए के अंतर्गत ग्राम सभा को जल की बजटिंग का कार्य सौंपा गया, जिसके तहत ड्रान जैसी नवीन तकनीक के माध्यम से जल स्रोतों का निर्माण कर उन पर नजर रखी जा रही है। वर्षा जल एवं भूमिगत जल को संचित करने की जिम्मेदारी लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई को सौंपी गई है।

इसके प्रथम प्रयास में 7742 गांवों ने 2.3 लाख तालाबों एवं बावडियों का निर्माण किया जबकि दूसरे फेज में 1.35 लाख जल संचय स्रोत 4213 गांव में निर्मित किये गये। इस प्रोग्राम के तहत 88 लाख लोग एवं 93 लाख जीव जंतुओं को 3350 हैक्टेयर क्षेत्र में पेयजल का लाभ हुआ।

वही तेलंगाना में मिशन काक्तेय में जल के संचय हेतु टैंक निर्माण का कार्य किया गया। वर्ष 2014 में प्रारम्भ इस प्रोग्राम के तहत वर्ष 2018 तक कृष्णा एवं गोदावरी बेसिन से 22500 टैंकों का निर्माण किया जा चुका है जो राज्य के 20 लाख एकड़ भूमि के जल संचयन में मदद कर रहे हैं।

वहीं उत्तर प्रदेश के जखनी गांव के किसानों कभी सूखायुक्त घोषित अपने गांव को अपने दृढसंकल्प से आज राज्य में जल संचयन का केंद्र बना दिया है। उन्होंने बिना किसी बाहरी मदद के खेतों में तालाब निर्माण कर वर्षा जल संचय, पुरानी बावडियों का जीर्णोद्धार, खेतों बाड़ बंदी तथा अतिरिक्त वृक्ष लगाकर भूमिगत जल स्तर का लेवल बढ़ाया। आज यह गांव अकेला 23 क्विंटल धान का उत्पादन करता है।